मारुति लिमिटेड और इसकी सहयोगी कम्पनियों को टेलीफोन कनेक्शन देना

602. श्री कर्पूरी ठाकुर : क्या संचार मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गुड़गाव (हरियाणा) में मारुति तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों को कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं और प्रत्येक कनेक्शन किस तिथि को दिया गया ;

(ख) क्या मारुति लिमिटेड के आस-पास 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित अन्य कारखानों के नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र लम्बे समय से लम्बित है और यदि हां, तो ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में आवेदकों को नए टेलिफोन कनेक्शन देने के लिए सरकार क्या कारवाई कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) गुड़गाव में मारुति लिमिटेड और उसकी सहयोगी कम्पनियों को बारह टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें से 8 टेलीफोन कनेक्शन दिल्ली टेलीफोन प्रणाली से जुड़े हैं और 4 कनेक्शन गुड़गांव एक्सचेंज से जुड़े हैं। एक कनेक्शन सितम्बर, 1971 में, तीन कनेक्शन मई, 1972 में, चार कनेक्शन जून, 1972 में, एक कनेक्शन मार्च, 1973 में और तीन कनेक्शन जनवरी, 1977 में दिए गए थे। मारुति लिमिटेड और उसकी सहयोगी कम्पनियों को दिल्ली से दिए गए 8 कनेक्शनों में से 5 कनेक्शन 1977 से पहले अर्थात् 1971 1972 में दिए गए थे। ये कनेक्शन सरकार के अधिकारों के अन्तर्गत बगैर ओ-वाई-टी के बिना बारी की प्राथमिकता के आधार पर दिए दिए गए थे। डाक-तार महानिदेशालय का पत्र सं० एफ 18-12/73-पी-एच-ए (आई-आर 1117,73 पी० एच ए) तारीख 8/11 73 है। बाकी तीन कनेक्शन जनवरी, 77 में दिए गए थे। टेलीफोन की ये मांगें 22,10/75 को सूची में दर्ज की गई थीं। मारुति लिमिटेड में 520 लाइन का पी बी-एक्स था जिसे बदल कर वे 850 लाइन का पी-ए-बी-एक्स लगाना चाहते थे। ये तीन कनेक्शन अधिक क्षमता वाले बोर्ड के लिए अतिरिक्त जंक्शनों के लिए थे।

(ख) जी हां। ऐसी 43 अर्जियां बकाया हैं। 13 अर्जियां दिल्ली से टेलीफोन कनेक्शनों के लिए है और 30 अर्जियां गुडगांव एक्सचेंज से टेलीफोन कनेक्शनों के लिए है।

(ग) गुडगांव एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाई जा रही है और जमीदोज केबुल बिछाए जा रहे हैं। आशा है कि गुडगांव से टेलीफोन कनेक्शन वर्ष 1978 के मध्य तक दे दिए जाएंगे।

दिल्ली कैंट एक्सचेंज की क्षमता बढ़ जाने पर उम्मीद है कि दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन वर्ष के 1979 के मध्य तक दे दिए जाएंगे।

मानतलाई के निकट धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आश्रम को टेलीफोन सुविधाएं

603. श्री जी० एस० तोहरा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानतलाई (जम्मू-कश्मीर) के निकट स्थित आश्रम में

श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को संचार विभाग के नियमों का उल्लंघन कर टेलीफोन सुविधाएं दी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर कितना खर्च हुआ ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी नहीं। टेलीफोन कनेक्शन विभाग के नियमानुसार दिया गया था।

(ख) किराए और गारंटी के आधार पर तारीख 5-3-1973 को एक लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० से एक्सटेंसन दिया गया था।

(ग) एक्सटेंशन देने पर 7400 रुपए खर्च आया था और सालाना किराया 1456 रुपए उक्त खर्च के आधार पर निश्चित किया गया है। पी० सी० ओ० भी तारीख 4-3-73 को 84,715 रुपए की लागत पर खोला गया था।

Progress of Salem Steel Plant during 1977

604. SHRI C. N. VISVANATHAN:
SHRI K. RAMAMURTHY:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state the progress of Salem Steel Plant during 1977 and whether any further allocation of money has been made for the completion of the plant?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): In March, 1977, Government gave approval for the first stage of Salem Steel Project involving an investment of Rs. 126.81 crores. Necessary preparatory work and infra-structure facilities for the first stage of the project have been almost completed. Expenditure incurred on the project so far amounts to Rs. 13.30 crores.

Offers have been received from international stainless steel makers for supply of production know-how.

An allocation of Rs. 13.07 crores has been proposed for the project during the current financial year.

Restoration of "Realignment Scheme" in P&T

605. SHRIMATI BIBHA GHOSH GOSWAMI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the previous Government had arbitrarily flouted the "Realignment Scheme" agreed to by the Government and the P&T Unions in 1954 which brought about one Federation (NFPTE) in P&T with 9 affiliated unions, by floating a parallel organisation immediately following the 1968 strike;

(b) if so, whether the new Government are contemplating to restore the "Realignment Scheme" in the P&T; and

(c) whether Government are considering restoration of recognition to elected office bearers of NFPTE and some of its affiliates which was withdrawn by the previous Government and granted recognition to parallel bodies?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No. Sir; The "Realignment Scheme" was agreed to in 1954. Following the September, 1968 strike when the NFPTE and its affiliated unions were derecognised, the staff organised themselves into new unions. These new unions affiliated themselves to the new Federation, FNPTO. Later the NFPTE was re-recognised in Nov. 1969, but since the FNPTO and its affiliated unions were already in existence they continued to be recognised.

(b) No such action is under consideration.

(c) There were disputes in the NFPTE and four of its affiliated unions. The disputes in NFPTE and